हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 43 | लखनऊ | रविवार 31 अक्टूबर 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया



उप्र को मिलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली एजेंसी। उत्तर प्रदेश को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन 31 अक्टूबर को शुरू की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में इसे हरी झंडी दिखाएंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन का उद्देश्य रात में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध कराना है। करीब 966 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह ट्रेन वाराणसी से रात में रवाना होकर अगले दिन सुबह दिल्ली पहुंचेगी। नियमित परिचालन के लिए प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार यात्रा में लगभग नौ घंटे लगेंगे। वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की प्रीमियम रात्रिकालीन रेल सेवाओं की नई कड़ी है। अब तक वंदे भारत ट्रेनों की पहचान मुख्य रूप से दिन के समय चलने वाली चेयरकार सेवाओं के रूप में रही है। स्लीपर संस्करण को लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि यात्री रात में सोते हुए सफर कर सकें और सुबह अपने गंतव्य पर पहुंच सकें। इस ट्रेन से वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर के यात्रियों को राजधानी दिल्ली आने-जाने के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। धार्मिक यात्रा, कारोबार, शिक्षा, नौकरी और पर्यटन के सिलसिले में दोनों शहरों के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए भी यह सेवा उपयोगी होगी। रेलवे की प्रस्तावित समय-सारणी के मुताबिक वाराणसी से ट्रेन संख्या 27421 रात 8:50 बजे रवाना होगी। यह रात 10:35 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद 10:40 बजे आगे बढ़ेगी। इसके बाद ट्रेन कानपुर सेंट्रल से होकर अगले दिन सुबह 5:55 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 27422 नई दिल्ली से रात 9:40 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन सुबह 4:45 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और पांच मिनट के ठहराव के बाद वाराणसी के लिए रवाना होगी। इसके सुबह 6:45 बजे वाराणसी पहुंचने का समय निर्धारित किया गया है। यह सेवा सप्ताह में छह दिन चलाने की योजना है। वाराणसी से शुक्रवार और नई दिल्ली से शनिवार को ट्रेन का नियमित संचालन नहीं होगा। हालांकि, उद्घाटन के दिन ट्रेन की विशेष सेवा और नियमित वाणिज्यिक परिचालन की समय-सारणी अलग होगी। उद्घाटन के लिए प्रस्तावित विशेष सेवा वाराणसी से शाम 4:30 बजे रवाना होकर रात करीब 1:30 बजे नई दिल्ली पहुंचने वाली है। नियमित सेवा के लिए यात्रियों को रेलवे की अंतिम समय-सारणी और बुकिंग संबंधी घोषणा का इंतजार करना होगा। ट्रेन में कुल 16 वातानुकूलित कोच होंगे। इनमें प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का एक, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के चार और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी के 11 कोच शामिल हैं। इनकी कुल यात्री क्षमता करीब 823 होगी। अलग-अलग श्रेणियों की व्यवस्था यात्रियों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सफर का विकल्प देगी। स्लीपर बर्थ होने के कारण लंबी दूरी के यात्री यात्रा के दौरान आराम कर सकेंगे।

प्रधानमंत्री गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर

प्रधानमंत्री 14 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात



नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 24वीं किस्त के रूप में देशभर के किसानों को करीब 19,000 करोड़ रुपये जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी जानकारी के अनुसार, मोदी 30 अक्टूबर को बनासकांठा में भ्रूण प्रत्यारोपण प्रौद्योगिकी एवं इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (ईटी-आईवीएफ) प्रयोगशाला और भारत गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद वह विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, दो रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी बनासकांठा के भिलड़ी में स्थापित भारत गोवंश प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 127 एकड़ में फैला यह केंद्र गोवंश की नस्लों में सुधार, आनुवंशिक उन्नयन और आधुनिक प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देगा। यह कांकरेज नस्ल के गोवंश के लिए देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा। इसके माध्यम से नस्ल सुधार की गति 10 से 20 गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री बनास डेयरी के थराद और राधनपुर में स्थापित होने वाले दो बायो-सीएनजी संयंत्रों की आधारशिला भी रखेंगे। इन संयंत्रों में प्रतिदिन क्रमशः 75 और 100 मीट्रिक टन गोबर के प्रसंस्करण की क्षमता होगी। मोदी अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण के तहत हवाई अड्डे और गिफ्ट सिटी तक विस्तार वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र ने बदली उप्र की तस्वीरः मुख्यमंत्री योगी



लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के जरिये प्रदेशवासियों को 2017 के पश्चात सड़क, रेल, मेट्रो व एयर कनेक्टिविटी की अभूतपूर्व बढ़ोतरी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। 2017 से पहले दयनीय थी स्थिति मुख्यमंत्री ने लिखा कि सड़क, रेल और हवाई संपर्क केवल दूरियां नहीं घटाते, बल्कि ये सुविधा, समय की बचत और समृद्धि की नई संभावनाएं लेकर आते हैं, लेकिन वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की इन जीवन रेखाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। प्रदेश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने स्पीड, स्केल और कनेक्टिविटी के मंत्र से इस तस्वीर को बदला है। भाजपा की डबल इंजन सरकार बनने से पहले देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में मात्र डेढ़ एक्सप्रेस-वे थे। आज प्रदेश में 10 एक्सप्रेस-वे संचालित हैं। तब हवाई सेवाएं चुनिंदा शहरों तक सिमटी थीं, लेकिन आज 12 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से प्रदेश की उड़ान नई ऊंचाइयों पर है। तब प्रदेश के एक भी शहर में मेट्रो नहीं चलती थी। वहीं, आज 7 शहरों में मेट्रो जनजीवन को नई गति दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परिवर्तन से किसान की उपज को बड़ा बाजार और उद्यमिता को नए अवसर मिल रहे हैं।

योगी सरकार ने बदले चरित्र प्रमाणपत्र के नियम

- **लखनऊ, (संवाददाता)।** उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए चरित्र सत्यापन की नीति सख्त की है। अब केवल एफआईआर से अभ्यर्थी अयोग्य नहीं होगा, अपितु कई अन्य मापदंड भी तय कर दिये गये हैं। सत्यापन रिपोर्ट 30 दिनों में देनी होगी और प्रतिकूल रिपोर्ट पर पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। चरित्र सत्यापन पूरा होने से पहले प्रोविजनल नियुक्ति दी जा सकेगी, लेकिन संवेदनशील और सुरक्षा से जुड़े पदों पर नियुक्ति से पहले विस्तृत जांच अनिवार्य होगी। प्रमुख सचिव एम देवराज ने बुधवार को इस संबंध में नई नीति जारी की है। नई नीति सरकारी विभागों के साथ निगम, परिषद, शैक्षणिक संस्थान, स्वायत्त निकाय, उपक्रम, पंचायत और स्थानीय निकायों की सीधी भर्तियों पर लागू होगी। लंबित मामलों का निस्तारण भी इसी नीति के तहत होगा। अभ्यर्थी का सत्यापन पुलिस महानिदेशक (अभिसूचना), गृह जिले और पिछले 5 वर्षों में एक साल से अधिक रहने वाले जिलों से कराया जाएगा। सामान्य मामलों में पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच होगी और भौतिक उपस्थिति या पूछताछ जरूरी नहीं होगी। प्रतिकूल रिपोर्ट आने पर अभ्यर्थी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

यूपी के अमेठी में खस्ता खाने से 102 लोग बीमार

अमेठी, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत कोटवा ग्राम सभा में एक मेला के दौरान खस्ता खाने के बाद सौ से अधिक बच्चों और वयस्कों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर मरीजों का परीक्षण किया और दवाएं वितरित की। 17 लोगों को मेडिकल कॉलेज तिलोई भेजा गया है। अमेठी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने गुरुवार को बताया कि ग्राम प्रधान की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तत्काल गांव पहुंची। उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने कुल 102 लोगों का परीक्षण कर उन्हें दवाएं दीं हैं। इनमें 39 बच्चे और 63 वयस्क शामिल हैं। यह फूड प्वाइजनिंग का मामला है। उल्टी की शिकायत अधिक होने और दवा से राहत नहीं मिलने के कारण 17 लोगों को मेडिकल कॉलेज तिलोई भेजा गया है। इनमें 10 बच्चे और 7 वयस्क शामिल हैं। फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर है और वे स्वस्थ हैं। विभाग की ओर से गांव में घर-घर जाकर दवाएं वितरित की गईं। साथ ही लोगों को साफ-सफाई, खानपान और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल स्थिति सामान्य है। गांव में बीमार लोगों की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस मामले में पिस्तौल सप्लायर की तलाश जारी



नई दिल्ली, (एजेंसी)। फिल्म अभिनेता टाइगर श्राफ फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस इस मामले में प्रयोग में लाई गई पिस्तौल मुहैया कराने वाले की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इस मामले में अब तक 11 आरोपितों को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गिरफ्तार किया गया है। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। इस मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मुंबई में 18 अक्टूबर को अभिनेता टाइगर श्रॉफ फायरिंग के मामले में पुलिस हथियारों को मुहैया कराने वाले नेटवर्क की जांच की जा रही है। अब तक जांच में पता चला है कि तीन आरोपितों ने कथित तौर पर अमृतसर से 2.50 लाख रुपये में जिगाना पिस्तौल और 20 गोलियां खरीदी थीं। जांच में सामने आया है कि कुणाल, सुमित और जतिन कथित तौर पर अनिल पंडित के कहने पर अमृतसर गए थे। तीनों ने वहां एक अज्ञात व्यक्ति से पिस्तौल और गोलियां खरीदीं तथा इसके बदले तय रकम दी थी। क्राइम ब्रांच अब हथियार सप्लाई करने वाले व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

'ऑपरेशन सिंदूर' से मजबूत हुई भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई : राजनाथ

भारत अपने साझेदारों के साथ सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध



नई दिल्ली एजेंसी। फिलीपींस के सेबू में 13वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक-प्लस (एडीएमएम-प्लस) में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई सिर्फ थ्योरी वाली नहीं है, बल्कि दशकों के जमीनी अनुभव और सफल ऑपरेशन से और मजबूत हुई है। %ऑपरेशन सिंदूर% ने आतंकवादी ढांचे को खत्म करके दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्का इरादा दिखाया। भारत अपने साझेदारों के साथ यह अनुभव साझा करके सुरक्षित, स्थिर और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में शामिल राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के सामने कहा कि भारत और आसियान की युवा आबादी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी सामर्थ्य को नई दिशा देने के लिए भारत ने मजबूत %डिफेंस यूथ ब्रिज% स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जो पीपल-टू-पीपल कनेक्टिविटी, डिजिटल इनोवेशन और कैपेसिटी-बिल्डिंग को बढ़ावा देगा। युवाओं को सशक्त बनाकर हम एक सुखद, स्थिर और समृद्ध इंडो-पैसिफिक के भविष्य को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि %सर्वे भवन्तु सुखिनः% की भावना भारत की रक्षा और विदेश नीति का मूल आधार है। एडीएमएम-प्लस की थीम %हमारे भविष्य को एक साथ आगे बढ़ाना% साझा जिम्मेदारी, आपसी विश्वास और सहयोग के महत्व को दर्शाती है। भारत खुला, समावेशी और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आसियान की केंद्रीय भूमिका और भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण हैं। भारत ने दशकों से भारतीय नौसेना के माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार और महत्वपूर्ण समुद्री संचार लाइनों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। एक विश्वसनीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत नेविगेशन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून के सम्मान के साथ सुरक्षित एवं स्थिर इंडो-पैसिफिक के लिए प्रतिबद्ध है। राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के सभी रूपों के उन्मूलन और सामूहिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद-रोधी अभियानों में भारत का व्यापक अनुभव केवल कक्षा तक सीमित सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि सीमा पार की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का दशकों तक सीधे सामना करके धरातल पर अर्जित किया गया अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत की प्रत्येक रणनीति को वास्तविक परिस्थितियों में संचालित अभियानों के दौरान परखा गया है, उसे और अधिक प्रभावी बनाया गया है तथा उसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है। उन्होंने कहा कि भारत के इस सक्रिय और धरातल पर परखे गए सिद्धांत का निर्णायक प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ, जब भारत ने आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त किया।

ममता ने विपक्ष से किया भाजपा के खिलाफ एकजुटता का आह्वान



नई दिल्ली, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने वोट चोरी के खिलाफ आगामी एक नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की एकजुट महारैली का आह्वान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई प्रत्येक भारतीय के मतदान और चुनाव करने के अधिकार की रक्षा के लिए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रविवार दोपहर 12:30 बजे विपक्षी गठबंधन रामलीला मैदान में एकजुटता प्रदर्शित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में मतदान को लेकर उठी चिंताओं और कथित वोट लूट का जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस विषय पर खामोशी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर चिंताएं व्यक्त करते हुए बनर्जी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), मतदाता डेटा, मतदाता सूची और मतगणना प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सीधे सवाल खड़े किए। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करते हुए उन्होंने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और नागरिक समाज के सदस्यों से इस महारैली में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। अपनी पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि जब लोगों के वोट और लोकतांत्रिक अधिकार खतरे में हों। तो खामोश रहना कोई विकल्प नहीं हो सकता है, इसलिए सभी को मिलकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। इस बीच, इस महारैली को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लोगों को एक नवंबर के %दिल्ली चलो% मार्च के लिए राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है।

तमिलनाडु में 25 ठिकानों पर डीवीएसी की छापा

त्रिची (तमिलनाडु)। तमिलनाडु के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (डीवीएसी) ने आज पिछली डीएमके सरकार के पूर्व मंत्री केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापा मारा है। डीएमके के प्रमुख सचिव और पूर्व नगर प्रशासनमंत्री नेहरू के त्रिची के थिल्लई नगर स्थित आवास पर सुबह से अधिकारी तलाशी ले रहे हैं। यह कार्रवाई नेहरू के कार्यकाल में नगर प्रशासन एवं पेयजल आपूर्ति विभाग में 2,538 सहायक और कनिष्ठ अभियंता की नियुक्ति में अनियमितता की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच के तहत की गई है। सुबह तीन वाहनों में पहुंचे सतर्कता विभाग के 15 से अधिक कर्मचारियों ने थिल्लई नगर स्थित पूर्व मंत्री नेहरू के आवास और कार्यालय परिसर को नियंत्रण में लिया। इसके बाद सघन तलाशी शुरू की। नेहरू के चेन्नई, त्रिची समेत लगभग 25 से अधिक ठिकानों पर दबिश दी गई है। उनके आवास के बाद चेन्नई के राजा

सनातन भारत की आत्मा, प्रहार करने वाले बौद्धिक और सांस्कृतिक आतंकवादी : स्वामी रामदेव



हरिद्वार, एजेंसी। पतंजलि विश्वविद्यालय में गुरुवार को 52वें अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने किया। वहीं, योगगुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति, संस्कारों, वेद, दर्शन, प्राचीन ज्ञान परंपरा और सनातन ग्रंथों के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान स्वामी रामदेव ने सनातन को भारत की आत्मा बताते हुए इसके विरुद्ध टिप्पणी करने वालों को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सनातनी ग्रंथों में मिलावट का आरोप लगाते हुए उनके संरक्षण के लिए विद्वानों की बड़ी समिति गठित करने की बात भी कही।उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि भारतीय संस्कृति, धर्म और प्राचीन विद्याओं का संरक्षण कर इस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आवश्यक है। युवाओं को भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और तपोभूमि है। यहां से भारतीय दर्शन, संस्कृति और प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण का संदेश पूरे देश में पहुंचना चाहिए। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को भारतीय ग्रंथों के अध्ययन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आज के युवा यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को समझेंगे और उसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो उनके भीतर रामत्व और कृष्णत्व के भाव को विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने पर बल दिया। योगगुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन शाश्वत है और वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। सनातन को आधार बनाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए विकसित और वैभवशाली भारत का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सनातन भारत देश की आत्मा है। भारत की आत्मा पर प्रहार करने वाले लोगों को उन्होंने बौद्धिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आतंकवादी बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का आतंक नहीं चलने दिया जाएगा।

त्रिपुरा में 200 कारतूस के साथ बांग्लादेशी हथियार तस्कर गिरफ्तार

अगरतला। त्रिपुरा पुलिस ने गुरुवार को गोमती जिले के उदयपुर स्थित महारानी थाना क्षेत्र में एक संदिग्ध हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 200 कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बिमल चकमा के रूप में हुई है, जो बुभांता चकमा का पुत्र है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपित बांग्लादेश के खगराछड़ी जिले के पंचहरी क्षेत्र के डुडुकछड़ा स्थित शांतिटिला का निवासी है। उस पर बांग्लादेश स्थित जनसंहति समिति (जेएसएस) के संतु गुट से जुड़े होने का संदेह है। आरोप है कि वह बिमल चकमा, प्रत्युत्तर चकमा और समाजप्रिय चकमा के लिए काम करता है। इन दोनों के ज्योतिष्मान चकमा उर्फ बुलबुल से जुड़े होने की बात कही जा रही है। बुलबुल को जुम्मा लिबरेशन आर्मी का उप क्षेत्रीय कमांडर बताया जाता है।

जियो की छलांग और विकसित भारत की नई आर्थिक गाथा

दूरसंचार कंपनियों को सेवा की गुणवत्ता, उचित कीमत और उपभोक्ता हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। टाटा, एयरटेल और दूसरे भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा भी इस क्षेत्र को अधिक सक्षम बना सकती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती–विकसित भारत के निर्माण में सरकार, उद्योग, निवेशक, श्रमिक और उपभोक्ता सभी की भूमिका है। रिलायंस के सामने भी भविष्य की कसौटियाँ कम नहीं हैं। बड़े बाजार मूल्यांकन को निरंतर नवाचार, टिकाऊ मुनाफे, रोजगार सृजन और जनविश्वास में बदलना होगा।

-: ललित गर्ग:-
****



उदाहरण है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश के बाद उसने इंटरनेट सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने, डेटा की कीमतों में व्यापक बदलाव लाने और डिजिटल गतिविधियों को आम नागरिक तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जियो की असली उपलब्धि केवल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी का दायरा विस्तृत करना है। रिलायंस की सफलता को मुकेश अंबानी के नेतृत्व में विकसित दीर्घकालीन कारोबारी दृष्टि, बड़े निवेश और बदलते समय के अनुरूप व्यवसाय का विस्तार करने की रणनीति के संदर्भ में समझना चाहिए। धीरूभाई अंबानी ने जिस उद्यमशीलता को व्यापक जनभागीदारी और पूँजी बाजार से जोड़ने की नींव रखी, उसे आगे बढ़ाते हुए समूह ने पेट्रोकेमिकल, ऊर्जा, खुदरा व्यापार और दूरसंचार जैसे विविध क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की। जियो ने इस विरासत को डिजिटल युग की आवश्यकताओं से जोड़ा। इस यात्रा का संदेश स्पष्ट है-समय के साथ जो नहीं बदलता, समय उसे पीछे छोड़ देता है, जो समय की आहट पहचान लेता है, वही भविष्य की दिशा तय करने लगता है। 28 अक्टूबर 2026 को जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में ऐतिहासिक सूचीबद्धता ने इस यात्रा को नया आयाम दिया। लगभग 30,213 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निर्गम के बाद कंपनी का बाजार पूँजीकरण 12.5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुँच गया और कारोबार के पहले दिन यह देश की दूसरी सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी बन गई। रिलायंस समूह की सूचीबद्ध कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य भी टाटा समूह से आगे निकल गया। ये आँकड़े भारतीय पूँजी बाजार के बदलते स्वरूप और डिजिटल अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को दर्शाते हैं। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि बाजार पूँजीकरण कंपनियों के मूल्यांकन का पैमाना है, आम नागरिक की समृद्धि का नहीं। शेयर बाजार में ऊँचाई तभी सार्थक है, जब उसका लाभ अर्थव्यवस्था की जड़ों तक पहुँचे। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रदत्त अनंत अंबानी का भावपूर्ण वक्तव्य चर्चाओं में हैं, उन्होंने इस व्यावसायिक उपलब्धि को पारिवारिक संस्कारों और आध्यात्मिक संवेदना से जोड़कर अर्थ के साथ अध्यात्म के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कारोबार की तुलना पूजा से और शेयरों को प्रसाद की तरह देश के साथ साझा करने की भावना से की। उनके शब्दों में कृतज्ञता, पारिवारिक विरासत और लाखों ग्राहकों के योगदान की स्वीकृति थी। मुकेश अंबानी का भावुक होना भी इस बात का प्रतीक था कि किसी बड़ी उपलब्धि के पीछे वर्षों का परिश्रम, संघर्ष, विश्वास और पीढ़ियों के सपने जुड़े होते हैं। यहाँ एक विचार विशेष रूप से उल्लेखनीय है-व्यापार केवल लाभ कमाने की व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास अर्जित करने का माध्यम भी है। जब कोई कंपनी अपनी सफलता में कर्मचारियों, तकनीशियनों, साझेदारों और उपभोक्ताओं के योगदान को स्वीकार करती है, तब उद्यम का मानवीय पक्ष सामने आता है। फलदार वृक्ष जितना ऊँचा होता है, उसकी शाखाओं में उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए। यही विनम्रता किसी कारोबारी साम्राज्य को स्थायी प्रतिष्ठा प्रदान करती है। अनंत अंबानी की पशुसेवा और वन्यजीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता भी इसी व्यापक सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में देखी जा सकती है। उद्योग की वास्तविक प्रतिष्ठा तब बढ़ती है, जब आर्थिक प्रगति के साथ जीवों के प्रति करुणा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता भी आगे बढ़े। दूरसंचार क्षेत्र की अग्रणी कम्पनी हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीएल) के संस्थापक एवं उद्योगपति महेंद्र नाहटा ने जियो के ऐतिहासिक लॉन्चिंग समारोह में सहभागिता करते हुए इसे भारतीय आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और आध्यात्मिक संवेदना का अनूठा संगम बताया। उनके अनुसार, जियो की यह उड़ान केवल एक कंपनी की व्यावसायिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल सामर्थ्य, उद्यमशीलता और वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा का प्रतीक है। उनके अनुसार अनंत अंबानी के आशीर्वाद, संस्कार और जनभागीदारी से जुड़े भावपूर्ण उद्बोधन ने इस आयोजन को मानवीय संवेदनाओं की विशिष्ट ऊँचाई प्रदान की। निस्संदेह, जियो की यह उड़ान नए भारत के आत्मविश्वास, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक अध्याय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, डिजिटल भुगतान, आधारभूत डिजिटल सुविधाओं और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने वाली पहलों ने देश के तकनीकी परिवर्तन के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। इस विकास में सरकार की नीतियों, निजी क्षेत्र के निवेश, वैज्ञानिक प्रतिभा और करोड़ों नागरिकों की भागीदारी का साझा योगदान है। जियो ने इस वातावरण का उपयोग करते हुए डिजिटल संपर्क का विस्तार किया। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी इसी व्यापक विकास यात्रा का हिस्सा है। परंतु आर्थिक आकार के साथ प्रति व्यक्ति आय, गुणवत्तापूर्ण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार भी उतना ही आवश्यक है। आगे की चुनौती और भी बड़ी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बादल आधारित संगणना, अंतरिक्ष से संपर्क और नई डिजिटल सेवाओं में निवेश भारत के लिए व्यापक अवसर पैदा कर सकता है। मगर तकनीक का लाभ तभी समावेशी होगा, जब ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत संपर्क, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत आँकड़ों की गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

संम्पादकीय

ट्रंप के मंसूबे पर पानी फिर गया

लूला की जीत से लैटिन अमेरिका में डोनरो डॉक्ट्राइन' लागू करने के अमेरिकी राष्ट्रपति के मंसूबे पर पानी फिर गया है। आरोप है कि लूला को हराने में ट्रंप समर्थकों ने पूरा जोर लगा रखा था। ब्राजील में तमाम चुनाव-पूर्व अनुमानों को धता बताते हुए लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा का फिर से राष्ट्रपति चुन लिया जाना दूरगामी वैश्विक महत्त्व की घटना है। तीन हफ्ते पहले प्रथम चरण के चुनाव में लूला धुर- दक्षिणपंथी उम्मीदवार फ्लावियो बोल्सोनारो से दो प्रतिशत वोट से पिछड़ गए थे। उसी रोज हुए संसदीय एवं प्रांतीय चुनावों में भी धुर-दक्षिणपंथी समूह को बड़ी जीत मिली थी। उसके मद्देनजर दूसरे चरण में लूला की जीत की संभावनाएं धूमिल थीं। लेकिन तीन हफ्तों में असाधारण चुनाव अभियान चला कर 80 वर्षीय लूला ने श्रमिक, मूलवासी, और प्रगतिशील तबकों की अभूतपूर्ण गोलबंदी की। उसका परिणाम उनकी जीत है, जिससे पूरे लैटिन अमेरिका में %डोनरो डॉक्ट्राइन' लागू करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के मंसूबे पर पानी फिर गया है। ट्रंप प्रशासन ने अपनी %सुरक्षा नीति' में लैटिन अमेरिका में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती-विहीन बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसमें उसे काफी सफलता मिली है। वहां एक के बाद दूसरे देश में ट्रंपवादी धुर-दक्षिणपंथी सरकारें हाल में सत्ता में आई हैं। अपवाद सिर्फ ब्राजील और मेक्सिको हैं। इसीलिए ब्राजील का चुनाव बेहद अहम हो गया था। गुजरे हफ्तों में ऐसी खबरें आईं कि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लेवियो के समर्थन में अमेरिका की बड़ी तकनीक कंपनियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। खासकर मेटा के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर बोल्सोनारो समर्थक सामग्रियों को खूब प्रसारित करने और लूला समर्थक सामग्रियों को प्रतिबंधित करने के आरोप लगे। ब्राजील का अभिजात्य वर्ग भी बोल्सोनारो के पक्ष में लामबंद था। चुनाव के दिन इल्जाम लगे कि कई राज्यों के दक्षिणपंथी नेताओं ने जानबूझ कर परिवहन सेवाओं में कटौती की। इतनी कि ऐन वक्त पर अदालत को मतदान का समय दो घंटे बढ़ाने का निर्णय देना पड़ा। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में लूला की संघर्ष भावना की जीत हुई है। इससे ब्रिक्स+ राहत की सांस लेगा। अंदेशा था कि बोल्सोनारो जीतते, तो विकासशील देशों के इस संगठन को कमजोर करने के ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाते। साथ ही लूला की जीत से उदारपंथी समूह उत्साहित होंगे, जो दुनिया भर में इस समय धुर-दक्षिणपंथ के आक्रामक तेवर के निशाने पर हैं।

न्यायपालिका की गरिमा व अनुशासन की लक्ष्मण रेखा

डॉ. अरविंद नाथ तिवारी
****



न्यायपालिका पर न्याय, निष्पक्षता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति आम नागरिक का विश्वास टिका होता है। न्यायालय के भीतर अनुशासन, पद की मर्यादा और परस्पर सम्मान का विशेष महत्व है लेकिन जब न्यायालय की कार्यवाही के दौरान किसी घटना को लेकर न्यायाधीश और अधिवक्ता के आचरण पर सवाल उठने लगता है तो यह केवल संबंधित व्यक्तियों तक सीमित विषय नहीं रह जाता बल्कि न्यायिक व्यवस्था की कार्य संस्कृति और संस्थागत गरिमा पर व्यापक बहस का कारण बन जाता है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय कक्ष संख्या-49 में न्यायमूर्ति अजय भनोट से संबंधित एक घटनाक्रम को लेकर अधिवक्ताओं के बीच असंतोष की चर्चा सामने आई है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, न्यायालय में एक जनपद के पुलिस अधीक्षक के प्रथम पंक्ति में बैठने और एक अधिवक्ता द्वारा उनसे पीछे बैठने का अनुरोध किए जाने के बाद विवाद उत्पन्न हुआ। बताया जाता है कि संबंधित अधिवक्ता के व्यवहार की शिकायत न्यायमूर्ति के समक्ष की गई। इसके बाद न्यायमूर्ति की प्रतिक्रिया, अधिवक्ता को जेल भेजने की कथित चेतावनी, पुलिस अधीक्षक से माफी मांगने के निर्देश और वरिष्ठ अधिवक्ता वी.पी. श्रीवास्तव के प्रति कथित टिप्पणी को लेकर अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई। इस घटनाक्रम के विरोध में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शिकायत करने तथा न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार का निर्णय लेने की बात भी सामने आई। हालांकि, इन घटनाओं के सभी पहलुओं की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना आवश्यक है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्य, परिस्थितियां और लागू न्यायिक नियमों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। फिर भी यह घटना कुछ बुनियादी सवाल खड़ा करता है, जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। पहला सवाल यह है कि न्यायालय के भीतर पुलिस अधीक्षक अथवा किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी के बैठने की व्यवस्था किस नियम और परंपरा के अनुसार निर्धारित होती है? क्या अधिकारियों के लिए अलग से कुर्सी या निर्धारित स्थान की व्यवस्था है? क्या प्रथम पंक्ति में बैठने का कोई विशेष प्रोटोकॉल है? यदि ऐसी व्यवस्था है तो उसका स्पष्ट पालन होना चाहिए ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी या अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। न्यायालय में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका और गरिमा होती है। न्यायाधीश न्यायिक कार्यवाही का संचालन करते हैं, अधिवक्ता पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी कानून के क्रियान्वयन एवं न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। किसी अधिकारी का प्रशासनिक पद उसे न्यायालय में अधिवक्ताओं से ऊपर कोई विशेष न्यायिक अधिकार नहीं देता। उसी प्रकार अधिवक्ता होने का अर्थ भी यह नहीं है कि वह न्यायालय के निर्धारित अनुशासन की उपेक्षा कर सकता है। इसलिए बैठने की व्यवस्था को प्रतिष्ठा अथवा पद की प्रतिस्पर्धा बनाने के बजाय स्पष्ट नियमों और समान रूप से लागू होने वाली परंपराओं के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश को न्यायालय की गरिमा बनाए रखने, अनुशासन कायम करने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने वाले व्यवहार पर विधिसम्मत कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की अवमानना से संबंधित कानून भी न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और कार्यप्रणाली की रक्षा के लिए मौजूद है लेकिन अधिकारों का प्रयोग करते समय संयम, निष्पक्षता और परिस्थितियों के अनुरूप प्रतिक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय में कोई अनुचित व्यवहार होता है तो उसकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव को समझकर कानून के अनुरूप कदम उठाना चाहिए। यदि किसी अधिवक्ता ने अनुचित भाषा का प्रयोग किया है तो उसे उचित प्रक्रिया के तहत समझाया जा सकता है या आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी अधिवक्ता को तत्काल जेल भेजने की चेतावनी दिये जाने अथवा माफी मांगने के लिए बाध्य किये जाने संबंधी आरोप सही पाये जाते हैं तो उन पर संस्थागत स्तर पर निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक होगी। न्यायाधीश का पद जितना अधिकारपूर्ण है, उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश और अधिवक्ता एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। न्यायाधीश को अधिवक्ता के तर्कों और कानूनी दलीलों को सुनना होता है, जबकि अधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह न्यायालय के प्रति सम्मान बनाए रखते हुए अपने मुवक्किल का पक्ष प्रस्तुत करे। दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन मतभेद को व्यक्तिगत टकराव में बदलना न्यायिक हित में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अनुभव और योगदान न्यायालय की कार्यसंस्कृति को समृद्ध करता है। दूसरी ओर, न्यायाधीश की गरिमा और न्यायिक अधिकारों का सम्मान भी न्यायिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। किसी एक पक्ष की गरिमा की रक्षा दूसरे पक्ष के सम्मान को ठेस पहुंचाकर नहीं की जा सकती। अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार का निर्णय लेना भी गंभीर विषय है, यदि अधिवक्ताओं को लगता है कि उनके सम्मान और अधिकारों की अनदेखी हुई है तो शिकायत दर्ज कराना, बार एसोसिएशन के माध्यम से अपना पक्ष रखना और मुख्य न्यायाधीश से निष्पक्ष हस्तक्षेप का अनुरोध करना संस्थागत समाधान की दिशा में कदम हो सकते हैं। न्यायालय की कार्यवाही के बहिष्कार से मुकदमों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विरोध का कोई भी तरीका अपनाते समय आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखना आवश्यक है। मर्यादा सबके लिए समान है इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय प्रश्न यही है कि क्या न्यायालय में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा की उपेक्षा की जा सकती है? इसका उत्तर स्पष्ट है-नहीं। अनुशासन आवश्यक है लेकिन उसके साथ निष्पक्षता और मानवीय मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। न्यायाधीश, अधिवक्ता और प्रशासनिक अधिकारी तीनों को अपनी-अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों का बोध होना चाहिए। अंततः न्यायालय की गरिमा किसी एक व्यक्ति के अधिकार से नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी के संयम, सम्मान और संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन से बनती है। जब न्यायाधीश का विवेक, अधिवक्ता की मर्यादा और प्रशासनिक अधिकारी का अनुशासन एक साथ कायम रहते हैं, तभी न्याय की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है। यही वह संतुलन है, जिसके टूटने पर केवल न्याय कक्ष का

आज का राशिफल

मेष निकट संबंधों में शंकाओं को हावी न होने दें। भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति होने के आसार बनेंगे। नौकरी का वातावरण सुखद होगा। सगे-संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी।

वृषभ आर्थिक क्षेत्र में लाभ के आसार हैं। अवरोधित कार्य हल होंगे। योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए ग्रहों की अनुकूलता लाभप्रद होगी।

मिथुन नकारात्मक चिंताओं का त्याग करें। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अपनी पूर्ति हेतु मन पर दबाव बनाएंगी। वर्तमान में आपको सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में प्रयास करना चाहिए।

कन्या किसी नये कार्य की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए मन केंद्रित होगा। नवीन योजनाओं द्वारा प्रगति होगी। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

धनु मन सुंदर कल्पनाओं से प्रभावित रहेगा। नये संबंधों के प्रति निकटता बढ़ेगी। उपस्थित साधनों में सन्तुष्ट व तृप्त होने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता अपेक्षित है।

मकर विभागीय परिवर्तनों से कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपने अन्दर धैर्य व वाणी में मधुरता लावें। कुछ नई अभिलाषाएं मन में जागृत होंगी। प्रियजनों का सन्निध्य प्राप्त होगा।

कर्क संबंधों में कटु वचनों का प्रयोग न करें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अच्छे कायरे द्वारा प्रशंसा के पात्र बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को ग्रहों की अनुकूलता का लाभ मिलेगा।

सिंह बीती बातों को भूलने की कोशि करें। रोजगार में कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। भौतिक इच्छाएं बलवती होंगी। अभिभावकों के भावनात्मक सहयोग से उत्साह में वृद्धि होगी।

तुला महत्वाकांक्षाएं मन पर प्रभावी होंगी। घरेलू कायरें में अत्याधिक व्यय का योग है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। परिवार में सुखद स्थिति प्रसन्नता लाएगी।

वृश्चिक परिश्रम का समुचित लाभ प्राप्त होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद व उत्साहपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।

कुंभ राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। अच्छे कायरे के लिए प्रशंसनीय होंगे। शासन-सत्ता से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा।

मीन आवेश में किये गये कार्य से कष्ट संभव। भावनात्मक समस्याओं पर सगे-संबंधियों के बीच खुलकर बात करें। कुछ नये उत्साह व कार्य क्षमता की अनुभूति करेंगे।

विज्ञान को विकसित भारत की आकांक्षाओं से जोड़ना

डॉ. जितेंद्र सिंह
****

समाज में परिवर्तन लाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार मुख्य रूप से विज्ञान से ही आएगा। 28 फरवरी 2006 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ये शब्द कहे थे। लगभग दो दशक बाद डॉ. कलाम के ये शब्द पूरी तरह सही साबित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक आधारित विकास को गति देते हुए %विकसित भारत' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की इस प्रगति पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है और उसने इसे स्वीकार भी किया है। विज्ञान का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि हम क्या खोजते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि हमारी खोजें देश के लोगों के लिए क्या-क्या संभव बनाती हैं। वैज्ञानिक प्रगति का वास्तविक मूल्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, समस्याओं का समाधान करने और नए अवसर पैदा करने की उसकी क्षमता में निहित है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाएं केवल आर्थिक विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं हैं। इनमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक उत्पादक कृषि, मजबूत उद्योग, युवाओं के लिए अधिक अवसर और प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार भी शामिल हैं। इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि हम जो ज्ञान विकसित करें, वह सार्थक बदलाव लाने का माध्यम बने यही उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) 2026 का व्यापक उद्देश्य है। अपने दूसरे संस्करण में ईएसटीआईसी वर्ष 2025 में शुरू हुए राष्ट्रीय संवाद को आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और उनके व्यावहारिक उपयोग के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के अग्रणी लोगों, स्टार्टअप से जुड़े उद्यमियों और युवा शोधकर्ताओं को एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए एक मंच पर लाता है। हमारे सामने कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ऐसे हैं, जिनका समाधान तत्काल आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रगति किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में किस तरह मदद कर सकती है? अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? भारतीय उद्योग उन्नत प्रौद्योगिकियां कैसे विकसित कर सकते हैं, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं और महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं? अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं? इन सवालों का जवाब कोई एक संस्थान या विषय अपने दम पर नहीं दे सकता। इसके लिए वैज्ञानिकों को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना होगा, शोधकर्ताओं को व्यावहारिक जरूरतों को समझना होगा और नीति निर्माताओं को ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें संभावनाओं से भरे विचारों को परखा और विकसित किया जा सके। ईएसटीआईसी 2026 इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 12 विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है। इनमें उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विज्ञान एवं समुद्री प्रौद्योगिकी, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, कृषि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, इमर्सिव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी संभावनाएं हैं, जिनका दायरा प्रयोगशालाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रगति भारत की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण के क्षेत्र में नए रास्ते खोल सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में होने वाले विकास औद्योगिक प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं, जबकि कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य अधिक कुशल एवं टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन संभावनाओं को व्यावहारिक उपयोग में बदलने की है। किसी वैज्ञानिक खोज में वर्षों का अनुसंधान लग सकता है, लेकिन उसे रोजमर्रा के उपयोग में लाने के लिए अक्सर आगे के परीक्षण, निवेश, इंजीनियरिंग और आपसी सहयोग की जरूरत होती है। हमें इस पूरी प्रक्रिया को मजबूत करना होगा, ताकि अनुसंधान से जुड़े शुरुआती सवाल से लेकर ऐसी तकनीक विकसित करने तक का सफर पूरा हो सके, जो वास्तविक लाभ पहुंचाए। भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं अंतत-उसके युवाओं की प्रतिभा और कल्पनाशीलता पर निर्भर करेंगी। किसी युवा शोधकर्ता के पास कोई संभावनाशील विचार है, तो उसे उसे प्रस्तुत करने, अनुभवी वैज्ञानिकों से सीखने और ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए, जो उस विचार को उपयोगी रूप देने में मदद कर सकें। ईएसटीआईसी 2026 %फ्रंटियर्स इन फोकस' सत्रों और %यंग रिसर्चर्स एंड इनोवेटर्स पिच कॉर्नर' के माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। %नेक्स्ट-जेन डिस्कवरी एक्सपो' में भारत की अनुसंधान क्षमताओं और उभरते डीप-टेक तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि %इनोवेशन एक्सचेंज हब' तकनीकों और संभावित सहयोग के अवसरों पर संवाद को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्यमिता को तेजी से एक-दूसरे का पूरक बनना होगा। विशेष रूप से डीप-टेक उद्यमों को किसी तकनीक को बाजार तक पहुंचाने से पहले अक्सर विशेष बुनियादी ढांचे, धैर्य के साथ किए जाने वाले निवेश और निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है। अनुसंधान संस्थानों के पास वैज्ञानिक विशेषज्ञता है, स्टार्टअप उद्यमशीलता की ऊर्जा लेकर आते हैं, उद्योग जगत उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं और बाजार की जरूरतों को समझता है, जबकि निवेशक इस पूरी प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। जब ये सभी क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो अनुसंधान को उपयोगी उत्पादों और सेवाओं में बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

ईएसटीआईसी 2026 ऐसी साझेदारियों को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। इसके तकनीकी सत्रों और प्रदर्शनियों का उद्देश्य केवल उपलब्धियों को प्रदर्शित करना नहीं है, बल्कि ऐसे संवाद और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना भी है, जिनसे आपसी सहयोग के नए रास्ते खुल सकें।

संक्षिप्त समाचार

सभी 669 राजकीय महाविद्यालयों की मासिक रैंकिंग जारी करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम बनाएं : वी. श्रीनिवास

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और निर्देश पर राज्य की सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्रम में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संवाद किया। इस दौरान एसपीसीजी कॉलेज अजमेर, राजकीय महाविद्यालय कोटा, एसबीआरएम राजकीय महाविद्यालय नागौर, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राज ऋषि राजकीय महाविद्यालय अलवर, एमएसजे राजकीय महाविद्यालय भरतपुर, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, महाराणा प्रताप पीजी राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चुरू के प्राचार्यों ने अपने-अपने महाविद्यालयों के संबंध में प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कक्षाकक्षों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों की जानकारी से मुख्य सचिव को अवगत कराया।

सीमावर्ती मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, शांतिपूर्ण चुनाव पर फोकस

श्रीगंगानगर, एजेंसी। पंचायती राज आम चुनाव-2026 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देशानुसार गुरुवार को श्रीगंगानगर एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी (आरओ) नयन गौतम के नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीओ सिटी नितिन चौधरी, सीओ ग्रामीण भूपेंद्र सिंह, बीडीओ भंवर लाल स्वामी, एसएचओ सदर सुभाष ढील एवं एसएचओ सुनील खोड ने कालिया, पतली, हिंदुमलकोट एवं तीन वाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन एवं पुलिस की ओर से पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियों पर ध्यान दिया जा रहा है।

विकास कार्यों के आधार पर यूपी में भाजपा के पक्ष में माहौल : एसपी सिंह बघेल

आगरा, एजेंसी । एमएलसी चुनाव के परिणाम को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने भाजपा के पक्ष में माहौल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, मुद्रा लोन, पेंशन और रोजगार के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का असर मतदाताओं पर दिखाई देगा। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को आवास और शौचालय मिले हैं। बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के तहत ऋण मिला है। विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन जैसी सुविधाओं से भी बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को इतिहास में सबसे अच्छा बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता के साथ बिना पैसे के भर्तियां हो रही हैं। उन्होंने नहरों में पानी की उपलब्धता, सड़कों के निर्माण और एक्सप्रेसवे के विस्तार का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। इन्हीं योजनाओं और विकास कार्यों के कारण आम मतदाताओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकारें बन रही हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का उल्लेख किया। साथ ही, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एनडीए की सरकार होने की बात कही। बघेल ने आगे कहा कि देश के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा के पक्ष में परिणाम आएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिश्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं और संगठन की मेहनत के आधार पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। बघेल ने भरोसा जताया कि कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकार की नीतियों से पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा।

दीपावली पर भजनलाल सरकार की किसानों को बड़ी सौगात, लगभग 345 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान

जयपुर, एजेंसी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 345 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान किया है। राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से प्राकृतिक आपदाओं एवं प्रतिकूल मौसम की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक संबल मिला है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा लंबित फसल बीमा दावों के निस्तारण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, चूरू, जालोर एवं डूंगरपुर जिलों के पात्र बीमित किसानों के फसल बीमा दावों के भुगतान की दिशा में



महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पश्चिमी राजस्थान के सूखा प्रभावित किसानों को बड़ी राहत, 318 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान कृषि आयुक्त ने बताया कि रबी 2025-26 के दौरान सूखे से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान के किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार ने अधिसूचित बीमा कंपनियों एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 318 करोड़ रुपये के फसल बीमा दावों का भुगतान करवाया है। इसके अंतर्गत बाड़मेर जिले के किसानों को 53.60 करोड़ रुपये, बीकानेर को 116 करोड़ रुपये, जोधपुर को 48 करोड़ रुपये, पाली को 31 करोड़ रुपये, चूरू को 25.85 करोड़ रुपये तथा जालोर जिले के पात्र किसानों को 43.58 करोड़ रुपये का फसल बीमा दावा भुगतान किया गया है। इस पहल से सूखे के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। राज्य स्तरीय समिति के निर्णयों पर त्वरित कार्रवाई, 17.60 करोड़ रुपये का भुगतान गोयल ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हाल ही में आयोजित राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की आपत्तियों को अस्वीकार करते हुए डूंगरपुर एवं जालोर जिलों के किसानों को 17.60 करोड़ रुपये के लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। कृषि विभाग ने इन निर्णयों की तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए जालोर जिले के खरीफ 2024 के लंबित फसल बीमा दावों के 10.64 करोड़ रुपये तथा डूंगरपुर जिले के खरीफ 2025 के फसल बीमा दावों के 6.96 करोड़ रुपये संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दिए हैं। यह कार्रवाई किसानों के हितों की रक्षा तथा बीमा कंपनियों के स्तर पर लंबित प्रकरणों के प्रभावी निस्तारण के प्रति राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जयपुर जिले के किसानों को 9.50 करोड़ रुपये की राहत, उच्चतर औसत उपज के आधार पर हुआ भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जयपुर जिले की दूदू तहसील के किसानों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। खरीफ 2025 के दौरान दूदू तहसील की कुछ बीमा इकाइयों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित नहीं होने के कारण किसानों के फसल बीमा दावों का भुगतान अटका हुआ था। राज्य सरकार के प्रयासों से उच्चतर औसत उपज के आधार पर पात्र बीमित किसानों के लंबित फसल बीमा दावों के 9.50 करोड़ रुपये का भुगतान अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से करवाया गया है। इस निर्णय से लंबे समय से बीमा दावा भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे किसानों को आर्थिक राहत मिली है। किसानों की आर्थिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता : कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हितों के संरक्षण, कृषि क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण तथा खेती को सुरक्षित एवं लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 : 2022 में भाजपा ने गाजियाबाद जिले में किया लीन स्वीप, पांचों सीटों पर जीते प्रत्याशी

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए राज्य के गाजियाबाद जिले की राजनीति में हलचल तेज है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गाजियाबाद की सभी पांचों सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार भाजपा नीत एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गाजियाबाद जिले में कुल पांच विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद सदर और मोदीनगर शामिल हैं। 2022 में सपा और लोकदल के बीच गठबंधन था, जिसमें लोकदल को लोनी, मुरादनगर और मोदीनगर सीटें मिली थीं। हालांकि, भाजपा को जीत मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में लोनी सीट पर भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर 8 हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीते थे। उन्होंने लोकदल के मदन भैया को हराया था। जहां नंदकिशोर गुर्जर को कुल 1,27,410 वोट हासिल हुए, वहीं लोकदल प्रत्याशी को 1,18,734 वोट मिले। बसपा ने अखिल और कांग्रेस पार्टी ने मोहम्मद यमीन मलिक को प्रत्याशी बनाया था। पिछले चुनाव में इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार थे। इसी तरह मुरादनगर में भाजपा के अजीत पाल त्यागी ने विजय हासिल की, जिन्होंने लोकदल के सुरेंद्र कुमार मुन्नी को 97 हजार से अधिक वोटों से हराया था। अजीत पाल त्यागी के पक्ष में कुल 1,69,290 मतदाताओं ने वोट डाला था और लोकदल प्रत्याशी को कुल 72,195 वोट मिले। बसपा के अयूब खान 20,589 वोटों के साथ तीसरे और कांग्रेस के वीरेंद्र यादव 7,055 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे। यहां भी 2022 में कुल 10 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। साहिबाबाद में सुनील कुमार शर्मा ने भाजपा के टिकट पर 2.14 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा को हराया। सुनील कुमार शर्मा को कुल 3,22,882 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी के खाते में कुल 1,08,047 पड़े। बसपा ने अजित कुमार पाल और कांग्रेस ने संगीता त्यागी को प्रत्याशी बनाया था। गाजियाबाद सीट पर भाजपा के अतुल गर्ग ने 1.05 लाख से अधिक वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को मात दी थी। अतुल गर्ग को कुल 1,50,205 वोट मिले और सपा प्रत्याशी को कुल 44,668 वोट हासिल हुए।

नागपुर में अपनी जीत पर सीएम फडणवीस पर बरसी कांग्रेस, डिलीट पोस्ट को बनाया मुद्दा

मुंबई, एजेंसी । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने गुरुवार को नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के महत्वपूर्ण चुनाव में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला किया, जहां कांग्रेस ने सीट बरकरार रखी। कड़े मुकाबले वाले इस चुनाव का समापन 45 घंटे से अधिक चली लंबी मतगणना के बाद हुआ। कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहाले को 3,271 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। ??वंजारी को 67,231 वोट



मिले जबकि कोहाले को 63,960 वोट मिले। इस हार को भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि नागपुर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दोनों का गढ़ माना जाता है, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार के लिए जमकर प्रचार किया था। शुरुआती रुझानों के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों में हुए विधान परिषद चुनाव परिणामों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए एक पोस्ट साझा किया था। इसी भावना को दोहराते हुए, मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते हुए एक भी सीट न जीतने पर तंज कसा। हालांकि, नागपुर के अंतिम परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते ही फडणवीस ने तुरंत वह पोस्ट डिलीट कर दी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने के लिए सोशल मीडिया प्?लेटफॉर्म 'एक?स' का सहारा लिया। कांग्रेस ने लिखा, 'पोस्ट डिलीट करके फडणवीस ने एक बार फिर सावरकर की विरासत को दोहराया है। अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले ही बड़ा प्रहार करने का दिखावा करते हुए फडणवीस ने जल्दबाजी में पोस्ट कर दिया। हालांकि, वही तीर उन पर ही उल्टा पड़ गया! अंततः उन्हें पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने भानु कुमार शास्त्री, किरण माहेश्वरी की जयंती पर किया नमन

उदयपुर, एजेंसी । जनसंघ के संस्थापक सदस्य, पूर्व सांसद एवं खादी ग्रामोद्योग के पूर्व अध्यक्ष भानु कुमार शास्त्री एवं राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री, भाजपा की राष्ट्रीय नेता एवं नगर निगम की पूर्व सभापति किरण माहेश्वरी की जयंती व पूर्व उपसभापति वीरेन्द्र बापना की द्वितीय पुण्यतिथि पर गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में संगोष्ठी एवं पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। पुष्पांजलि सभा में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर पारस सिंघवी, जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, पूर्व जिलाध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक प्रमोद सामर, भानु कुमार शास्त्री के भाई पद्म शास्त्री, पार्षद जतिन श्रीमाली, प्रवक्ता गोविन्द दीक्षित, प्रकाश अग्रवाल,



किरण तातेड़ ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने भानु कुमार शास्त्री, किरण माहेश्वरी के आदर्शपूर्ण राजनीतिक जीवन, राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण में योगदान और जनसेवा के प्रति समर्पण को नमन करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि मेवाड़ में जनसंघ की स्थापना भानु कुमार शास्त्री ने की थी। भाजपा को पूरे देश में वट वृक्ष के रूप में पहुंचाने में शास्त्री जी और माहेश्वरी जी का अहम योगदान रहा है। वे त्याग, तपस्या और राजनीति में शुचिता की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में पार्षद से लेकर मंत्री तक का सफर किया, लेकिन अपने ऊपर कभी एक दाग नहीं लगने दिया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में दीपक से लेकर कमल को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया। इनकी कथनी एवं करनी में कभी फर्क नहीं रहा। अपने जीवन में हजारों कार्यकर्ताओं को गढ़ने का कार्य उन्होंने किया। पद की कभी चिंता नहीं की। उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि देश में कभी हमारा राज भी आएगा, लेकिन अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वक्ताओं ने कहा कि शास्त्री जी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, पूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया भी अपनी जन्म पत्रिका इन्हें बताने आया करते थे। किरण माहेश्वरी ने अपनी कार्यशैली से एक सामान्य कार्यकर्ता से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने एक महिला के रूप में राजनीति में जो मुकाम हासिल किया, वह सभी के लिए प्रेरणादायी है। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर महामंत्री देवीलाल सालवी, डॉ. पंकज बोराण, डॉ. सोनिका जैन, मंडल अध्यक्ष अमृत मेनारिया, कन्हैया वैष्णव, मुकेश जोशी, महेशपूरी गोस्वामी, रणजीत सिंह दिगपाल, पार्षद अशोक नागदा, लता नायक, देवनारायण धाबाई, करण सिंह शक्तावत, शैलेन्द्र चौहान, दिग्विजय श्रीमाली, जयंत ओझा, जगदीश सुथार, हजारी जैन, बाबुलाल ओड, किशन खटीक, सुरेन्द्र सिंह पंवार, कैलाश निमावत, गिरीश शर्मा, मांगु सिंह रावत, गणेश व्यास,, दुदाराम डांगी, माधुरी राठौड, सनी पोखरना, भंवर सिंह देवडा, खुशबू मालवीया, सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भानु कुमार शास्त्री, किरण माहेश्वरी एवं वीरेन्द्र बापना की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया।

रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर गरजी निगम की जेसीबी : 10 से 12 फीट तक फैला अतिक्रमण ध्वस्त, महापौर के औचक निरीक्षण के बाद सामान जब्त

उदयपुर, एजेंसी। दीपावली पर्व पर शहर में देशी-विदेशी पर्यटकों और यात्रियों की भारी आवाजाही को देखते हुए उदयपुर नगर निगम ने प्रमुख मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने का सख्त अभियान शुरू कर दिया है। गुरुवार को नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रेलवे स्टेशन के ठीक सामने कच्ची बस्ती के बाहर मुख्य सड़क पर फैले 10 से 12 फीट तक के अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ढहा दिया और मौके से सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम महापौर पारस सिंघवी खुद मौके पर डटे रहे और पूरे अभियान की निगरानी की। पार्षद की शिकायत पर महापौर ने किया औचक



निरीक्षण रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री शहर में दाखिल होते हैं: शिकायत पर संज्ञानः स्थानीय पार्षद वैभव भंडारी ने महापौर को अवगत कराया था कि रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती के बाहर कुछ लोगों ने मुख्य मार्ग पर 10 से 12 फीट तक अवैध कब्जे कर रखे हैं, जिससे आए दिन जाम लग रहा है और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर समझाइश बेअसरः शिकायत की गंभीरता को देखते हुए महापौर पारस सिंघवी गुरुवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। महापौर ने शुरुआत में कब्जाधारियों से समझाइश करते हुए सार्वजनिक मार्ग से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील की। जेसीबी से ध्वस्तीकरणः जब कब्जाधारियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं दिखाया, तो निगम के दस्ते ने नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी। जेसीबी की मदद से अस्थायी ढांचों और टीन-शेड को जमींदोज किया गया तथा सड़क सीमा में रखे सामान को जब्त कर लिया गया।

चावल घोटाले में मंत्री की भूमिका की भी जांच करे CBI : सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली , एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने चावल घोटाले में दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की भूमिका की भी जांच करने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक को एक पूरक शिकायत सौंपकर मंत्री को मामले की जांच के दायरे में शामिल करने और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित करने की अपील की है। भारद्वाज का आरोप है कि दिल्ली के गरीबों को वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले चावल को कथित तौर पर निजी कंपनियों के माध्यम से खुले बाजार में बेचा गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चावल की खरीद और आवंटन से संबंधित प्रस्तावों को बार-बार मंजूरी दी, लेकिन सीबीआई की प्राथमिकी में उनका नाम आरोपियों की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में विभागीय अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि उन अधिकारियों को कथित तौर पर निर्देश देने वाले मंत्री की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप नेता ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निलंबित अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा के लिखित जवाब का हवाला देते हुए दावा किया कि अधिकारी ने अपने जवाब में सात अलग-अलग स्थानों पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम लिया है। भारद्वाज के अनुसार, अधिकारी ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को भेजे गए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), प्रसंस्करण संबंधी निर्देश और अन्य प्रशासनिक मंजूरियां मंत्री के साथ चर्चा तथा उनके निर्देशों के बाद दी गई थीं। भारद्वाज ने कहा कि यदि किसी अधीनस्थ अधिकारी को कथित अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया जा सकता है, तो संबंधित निर्णयों को मंजूरी देने वाले वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने विभाग के कारण बताओ नोटिस का हवाला देते हुए दावा किया कि एफसीआई को भेजी गई कुछ सिफारिशों को विभाग ने अवैध और अनधिकृत बताया है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, नेरामेक ने 7 जनवरी 2026 को 31,000 मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री ने 8 अप्रैल 2026 को संबंधित प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार करने के निर्देश दिए।

दिल्ली प्रदूषण : पाबंदियां लागू होने के साथ 1 नवंबर से इन वाहनों के प्रवेश पर रोक

नई दिल्ली , एजेंसी । सर्दियों के मौसम में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के तहत 1 नवंबर से दिल्ली के बाहर पंजीकृत उन वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी, जो बीएस-VI मानकों का पालन नहीं करते हैं। यह पाबंदी 31 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग के अनुमानों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद शामिल हैं, वहां 10 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं, जो बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इन प्रस्तावित पाबंदियों का असर बड़ी संख्या में उन लोगों पर पड़ सकता है, जो काम, व्यापार या अन्य कारणों से नियमित रूप से आसपास के शहरों से राजधानी आते-जाते हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगभग दो लाख वाहन ऐसे हैं जो बीएस-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इनमें से करीब 70 प्रतिशत वाहन बीएस-III और बीएस-IV श्रेणी के हैं। हरियाणा के इन दो जिलों में लगभग 50,000 कमर्शियल वाहन भी ऐसे हैं, जो तय उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरते। उत्तर प्रदेश के



नजदीकी शहरी इलाकों में ऐसे वाहनों की संख्या और भी अधिक है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल मिलाकर चार लाख से अधिक ऐसे वाहन हैं, जो बीएस-VI मानकों को पूरा नहीं करते। इनमें से आधे से अधिक वाहन बीएस-IV श्रेणी के हैं, जिनमें पेट्रोल से चलने वाली कारों की संख्या सबसे ज्यादा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद में भी लगभग चार लाख वाहन ऐसे हैं, जो बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते। इससे पता चलता है कि सर्दियों के महीनों में दिल्ली में ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश को सीमित करना अधिकारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। हालांकि, इन अनुमानों में शामिल सभी वाहनों पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) और बिजली से चलने वाले वाहनों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा, एंबुलेंस, दमकल गाड़ियां और कुछ खास जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों को भी छूट मिलेगी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे वाहन जो बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ये पाबंदियां मुख्य रूप से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन वाहनों पर लागू होंगी, जो बीएस मानकों को पूरा नहीं करते। राष्ट्रीय राजधानी के भीतर रजिस्टर्ड वाहनों पर यह विशेष नियम लागू नहीं होगा, हालांकि वाहनों की उम्र से जुड़े अन्य मौजूदा प्रदूषण-नियंत्रण उपाय और नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। 1 नवंबर से लागू होने जा रहे प्रतिबंधों को देखते हुए, अधिकारी दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी और सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि तय उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले वाहनों को शहर में आने से रोका जा सके। प्रशासन सीमा चौकियों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर तकनीक-आधारित निगरानी प्रणालियों का उपयोग करने की योजना बना रहा है, ताकि नियमों का पालन न करने वाले वाहनों की पहचान की जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित 'ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन' कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करेंगे, जिससे अधिकारियों को ऐसे वाहनों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि यह निगरानी प्रणाली पड़ोसी इलाकों से राजधानी की ओर आने वाले वाहनों की पहचान करने में अहम भूमिका निभाएगी, खासकर उन रास्तों पर जो दिल्ली को नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से जोड़ते हैं और जहां वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है। निगरानी तकनीक तैनात करने के साथ-साथ, प्रशासन प्रवेश बिंदुओं पर भौतिक जांच और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर रहा है।

नितेश मिश्रा को मिली गोरखपुर क्षेत्र के सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी,बधाइयों का लगा तांता

जनता का सच-समाचार रिपोर्ट-राजेश 'महाजन' मंडल-प्रभारी,आजमगढ़-मंडल (बलिया,मऊ,आजमगढ़) मो०न०-08115659303

बलिया-भारतीय जनता पार्टी के बलिया जिला सोशल मीडिया संयोजक नितेश मिश्रा को उनके कार्यों और संगठन के प्रति योगदान को देखते हुए गोरखपुर क्षेत्र के सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके इस मनोनयन से पार्टी



कार्यकताओं में खुशी का माहौल है नितेश मिश्रा को नई जिम्मेदारी मिलने पर बांसडीह विधायक केतकी सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा,पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी,आनन्द स्वरूप शुक्ला, संजय यादव,देवेन्द्र यादव, हिमांशु प्रताप सिंह, आलोक शुक्ला,संजीव डम्पू, जयप्रकाश जायसवाल, संजीव सिंह, लवकुश मधेसिया , सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य नेताओं एवं कार्यकताओं ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की नेताओं ने विश्वास जताया कि नितेश मिश्रा अपनी नई जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा और सक्रियता के साथ करेंगे तथा सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यो को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।नितेश मिश्रा को मिली इस नई जिम्मेदारी को लेकर समर्थकों और पार्टी कार्यकताओं में उत्साह देखा जा रहा है

वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर हुई चर्चा

जनता का सच-समाचार रिपोर्ट-राजेश 'महाजन' मंडल-प्रभारी,आजमगढ़-मंडल (बलिया,मऊ,आजमगढ़) मो०न०-08115659303

बलिया-जनपद बलिया के कोषागार परिसर में वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण



कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोषागार परिसर के सौंदर्यीकरण एवं विकास से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई इस अवसर पर परिसर में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित करने, उच्च कोटि के विद्युतीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा परिसर में स्थित प्राचीन कुएँ के जीर्णोद्धार को लेकर विचार-विमर्श किया गया इन प्रस्तावित कार्यों का उद्देश्य परिसर को अधिक व्यवस्थित, सुंदर एवं सुविधाजनक बनाना है कार्यक्रम में परिसर के विकास कार्यों को बेहतर ढंग से संपन्न कराने तथा प्रस्तावित योजनाओं को आगे बढ़ाने के संबंध में आवश्यक चर्चा की गई। भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना से परिसर में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है वहीं, विद्युतीकरण और प्राचीन कुएँ के जीर्णोद्धार से परिसर की सुविधाओं में सुधार होगा वरिष्ठ कोषाधिकारी- आनंद दुबे के निर्देशन में प्रस्तावित इन कार्यों को लेकर सकारात्मक पहल की गई इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कोषागार परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ उसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्ता को भी संरक्षित करने में मदद मिलेगी

मायावती ने राजनीतिक बयानबाजी पर जताई चिंता, बोलीं- नेताओं के बीच बढ़ती कटुता देशहित में नहीं

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने भारतीय राजनीति में बढ़ती कटुता, व्यक्तिगत टिप्पणियों और अमर्यादित बयानबाजी पर चिंता जताई है। उन्होंने नेताओं से सार्वजनिक संवाद में मयार्दा बनाए रखने की अपील की। मायावती ने कहा कि राजनीतिक



दलों को आपसी टकराव के बजाय गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने भारतीय राजनीति में बढ़ती कटुता, आपसी अविश्वास और आरोप-प्रत्यारोप पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजी का स्तर अब व्यक्तिगत टिप्पणियों, अमर्यादित भाषा, जातिवाद और हिंसक बयानों तक पहुंचना दुखद है। इससे देश की गरिमा और राजनीतिक व्यवस्था पर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंच सकता है। मायावती ने कहा कि शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को किसी भी स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकीर्ण और गरीब-विरोधी स्वार्थों से प्रेरित राजनीति के कारण लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होना देश और जनहित में नहीं है। जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत बसपा प्रमुख ने कहा कि सरकारी स्तर पर भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नेताओं के बीच आपसी टकराव से राजनीतिक माहौल और खराब हो रहा है। जनता चाहती है कि राजनीतिक दल गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। वीडियो: खरगे की टिप्पणी से तराई में आक्रोश, कांग्रेस का फूंका पुतला; भाजपाई बोले- राजनीति में भाषा की मयार्दा बनाए रखना जरूरी अमर्यादित बयानबाजी से बचने की अपील मायावती ने कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बीच अशोभनीय टिप्पणियों और बयानबाजी की बढ़ती होड़ से माहौल और कड़वा होगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और नेताओं से इस पर गंभीरता से विचार करने तथा सार्वजनिक संवाद में मयार्दा बनाए रखने की अपील की।

70-वीं राष्ट्रीय विद्यालयी फुटबॉल प्रतियोगिता की बैठक हुआ संपन्न

जनता का सच-समाचार रिपोर्ट-राजेश 'महाजन' मंडल-प्रभारी,आजमगढ़-मंडल (बलिया,मऊ,आजमगढ़) मो०न०-08115659303



बलिया-टाउन इण्टर कॉलेज बलिया के हाल में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ डॉ राजेश कुमार आर्य ने की। बैठक में सभी समितियों के नोडल तथा उनके सदस्य उपस्थित रहकर अपने-अपने पदों के सापेक्ष दायित्व निर्वहन में पूर्ण रूप से तैयार रहने की बात की। मंडलीय क्रीडा सचिव एवं कि प्रतियोगिता के समन्वयक दिनेश कुमार सिंह द्वारा सभी समितियां के कार्य दायित्व एवं निर्वाहन पर प्रकाश डाला गया तथा बलिया की संस्कृति के अनुरूप देश के टीमों के खिलाड़ी मैनेजर तथा प्रशिक्षक सहित अन्य समस्त आगंतुक अतिथियों का स्वागत बलिया किस स्वीकृति के अनुरूप किए जाने की बात की गई और पिछले वर्ष 69 में राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता के सफल आयोजन में लगे हुए सदस्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की गई सभी सभी ने हम तैयार हैं का उद्घोष किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रतिनिधि माध्यमिक शिक्षा अधिकारी हनुमानगंज ने विभाग के समस्त शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं अनुदेशक को अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया श्री मनोज कुमार मिश्रा द्वारा माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के साथ साथ समस्त सहयोगियों का इस कार्यक्रम में कार्य करने हेतु मनोबल ऊंचा किया गया और अंत में बैठक की अध्यक्षता कर रहे संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय ने आजमगढ़ मंडल के बलिया में पिछले वर्ष जिस प्रकार से राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती का सफल आयोजन करते हुए जनपद का नाम रोशन किया गया इस प्रकार से इस बार भी अपने-अपने पद के सापेक्ष दायित्व का निर्माण पूरे मनोभाव से करते हुए सभी का बेहतरीन स्वागत और सभी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कमी न होने की बात कही गई साथ ही निर्देशित किया गया कि ड्यूटी में लगे हुए कोई भी सदस्य पदाधिकारी शिथिलता के साथ कार्य नहीं करेंगे। बैठक के उपरांत माननीय परिवहन मंत्री को उद्घाटन अवसर पर बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र मंत्री जी के प्रतिनिधि हर्ष सिंह एवं उनके अनुज धर्मेंद्र सिंह को संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय के द्वारा सौंपा गया। साथ ही सोनाडीह की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी कुमारी प्रिया और राष्ट्रीय खिलाड़ी निगम तथा सलोनी को अतिथि गण के साथ आशीर्वाद प्रदान किया गया। इस अवसर पर आयोजन समिति नोडल अधिकारी हिमांशु सिंह खंड शिक्षा अधिकारी चिलकहर राकेश कुमार सिंह खंड शिक्षा अधिकारी दुबहर विशाल यादव खंड शिक्षा अधिकारी गढ़वार तथा सह समन्वयक दिनेश प्रसाद, पंकज सिंह, अजीत सिंह, मनोज सिंह, अनुज कुमार, आजमगढ़ से अबरार अहमद, सत्यानंद मिश्रा राकेश पांडे राकेश पांडे के बाद जयप्रकाश गुप्ता राजन प्रताप प्रकाश राय विशाल यादव दानिश मोहसिन राकेश सिंह रजनी श्रीवास्तव सुमेधा पांडे गौरी वर्मा अनामिका सिंह चंदेल संगीता यादव साधना सोनकर अर्चना सिंह सीमा सिंह शबनम मारा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद कुमार सिंह ने किया।

अखिलेश बोले- कांति सिंह की सीट पर 97 बूथों पर बिना फोल्ड किए मिले वोट, भाजपा ने कराई बेईमानी

लखनऊ। अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में कांति सिंह की सीट के 97 बूथों पर बिना फोल्ड किए मिले वोटों को लेकर सवाल उठाए और भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाया। वहीं, धर्मेंद्र कश्यप ने पिछड़े वर्ग को न्याय नहीं मिलने की बात कही। उन्होंने कश्यप समाज के एक दर्जन से अधिक लोगों की हत्याओं का भी दावा किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव में सपा प्रत्याशी कांति सिंह की सीट पर मतदान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 97 बूथों पर बिना फोल्ड किए हुए वोट मिले हैं। अखिलेश ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पूरा डिब्बा वोट डालकर लाया गया होगा। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी कराने का आरोप लगाया। वहीं, धर्मेंद्र कश्यप ने पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज के एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है और इन घटनाओं में जाति विशेष के लोगों का हाथ है। धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि आज ने धर्मेंद्र कश्यप और उनकी बेटी कीर्ति कश्यप का सपा में स्वागत किया। उन्होंने



अखिलेश यादव जरूरी हैं और वह समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने विधान परिषद चुनाव में बैलेट बॉक्स में बिना फोल्ड किए बैलेट मिलने का दावा करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अखिलेश कहा कि धर्मेंद्र कश्यप के आने से पीडीए का संघर्ष मजबूत होगा और भाजपा चुनाव हारेगी। अखिलेश ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची दुरुस्त कराने की अपील की। उन्होंने मतदान में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने की मांग भी उठाई। उनका आरोप था कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के समर्थक मतदाता हैं, वहां लंबी कतारें लग रही हैं और केवल एक मशीन लगाकर मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि गोरखपुर में बिना सील का बॉक्स मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छोटी कार्रवाई के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों पर भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा बुनियादी सवालों पर बात नहीं करना चाहती। उन्होंने केसर चीनी मिल पर 162 करोड़ रुपये बकाया होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर 24 घंटे के भीतर भुगतान कराया जाएगा। अखिलेश ने कुछ राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि प्रीपेड पार्टियों से सावधान रहना होगा। उन्होंने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि कुछ दलों का ओटीपी कहीं और से आता है। माइक और लाउडस्पीकर किसी और के बनकर आते हैं। उन्होंने पतंग की डोर कटने का उदाहरण देते हुए भी राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने भाजपा पर वोट हासिल करने के लिए बड़ी कंपनियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कैमरों में रंगों को लेकर भी तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं कौन-सा लेंस लगाया जाता है, जिसमें लाल रंग भी भगवा दिखाई देता है।

हाथ जोड़ती हूं, सुमेधा की चीखों से भी नहीं पसीजा कातिल, आंखों के सामने उजड़ गया परिवार

लखनऊ में कार पार्किंग और चबूतरे के मामूली विवाद को लेकर पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने अंधाधुंध फायरिंग कर पूर्व कर्मचारी शिवाजी तिवारी, उनके भाई शंभू तिवारी और होने वाले दूल्हे बेटे सुयश तिवारी की हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि पुलिस की कथित लापरवाही के चलते तीन लोगों की जान चली गई। वहीं, शादी की खुशियां मातम में बदल गई। राजधानी लखनऊ में सआदतगंज के नौबस्ता स्थित ब्राह्मणी टोला में सोमवार सुबह शिवाजी तिवारी (60), उनके भाई शंभू तिवारी (55) और बेटे सुयश तिवारी (30) की पड़ोसी ऋषभ शुक्ला ने गोली मारकर हत्या कर दी। किसी ने नहीं सोचा था कि कार पार्किंग और बरगद के पेड़ का चबूतरा बनाने के लिए शुरू हुआ झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल जाएगा। मामूली विवाद में ऋषभ के सिर पर खून सवार हो गया था। पिता शंभू तिवारी को बचाने के लिए सुमेधा



ने उसके सामने हाथ तक जोड़े लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। सुमेधा गिड़गड़ाती रही और ऋषभ उसके पिता पर गोलियां दागता रहा। सुमेधा के आंखों के सामने उसका परिवार उजड़ गया। पुलिस की छानबीन में ऋषभ के परिजनों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। उसके चाचा राजेश शुक्ला के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई थी। यही वजह है कि राजेश को छह महीने के लिए जिलाबदर किया गया था। कोर्ट से स्टे लेने के बाद वह इलाके में खुलेआम टहलता रहता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि राजेश पुलिसकर्मियों के साथ भी नजर आता था। पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल सभी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो न होती वारदात चबूतरे के विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से थी। पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई होती तो शायद तीन लोगों की जान बच सकती थी। शिवाजी लगातार थाने में मामले की पैरवी कर रहे थे। बीते माह पार्षद ने चबूतरा बनाने का काम शुरू कराया था। इस पर ऋषभ ने मजदूरों की पिटाई कर दी थी। शिवाजी ने थाने में शिकायत की पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर के सामने थाने में दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। बावजूद इसके दोनों पक्षों को पाबंद भी नहीं किया गया। रविवार रात भी शिवाजी थाने गए थे लेकिन वहां ऋषभ के चाचा राजेश बैठे थे। पुलिसकर्मियों ने शिवाजी को बैरंग लौटा दिया। इसके अगले दिन वारदात हो गई। शिवाजी के परिवार में उनकी पत्नी उषा और शंभू तिवारी के परिवार में पत्नी रुचि व बेटी सुमेधा बचे हैं। शिवाजी तिवारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। मोहल्ले में उनके प्रभाव के कारण भी ऋषभ और उसके घरवाले रंजिश रखते थे। पांच दिसंबर को शिवाजी के बेटे सुयश की शादी थी। घर में इसकी तैयारियां चल रही थीं लेकिन पल भर में इसकी खुशियां मातम में बदल गईं। शंभू की पत्नी रुचि ने बताया कि 21 मई को सुयश की सगाई हुई थी। उसकी घर के पास ही इलेक्ट्रिक की दुकान है। वह शादी समारोहों में बिजली का ठेका भी लेता था। शिवाजी शक्ति भवन में स्टेनो पद से सेवानिवृत्त हुए थे। शंभू लखनऊ यूनिवर्सिटी में बड़े बाबू थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान ऋषभ के पिता दिनेश शुक्ला ने शिवाजी को डंडा मार दिया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया था। ऋषभ की बहनों ने भी पथराव शुरू कर दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी ऋषभ ने 10 से 12 राउंड गोली चलाई।

1.70 लाख से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिला कैशलेस चिकित्सा का तोहफा, कैबिनेट में मिली हरी झंडी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभागों के



1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मंजूरी दी है। योजना के तहत सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराया जा सकेगा। इस पर राज्य सरकार सालाना लगभग 51.11 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उत्तर प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा विभाग के 1,70,366 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत कर्मचारी सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ योजना से संबद्ध निजी अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार वहन करेगी 51.11 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि योजना के लिए राज्य सरकार प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम देगी। इस पर कुल 51.11 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा। योजना का संचालन स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (साचीज) के माध्यम से किया जाएगा। कैशलेस उपचार की सुविधा इनडोर पेशेंट डिपार्टमेंट (आईपीडी) यानी अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले इलाज के लिए होगी। उपचार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की अनुमोदित दरों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा के 1.22 लाख कर्मियों को लाभ बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों, वित्तविहीन विद्यालयों और समग्र शिक्षा परियोजना में कार्यरत 1,22,304 शिक्षणेत्तर कर्मचारी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। इनके लिए सरकार लगभग 36.69 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रीमियम वहन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस, 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा परिवार को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की थी। कैबिनेट की मंजूरी के साथ इस घोषणा को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा के 48 हजार से अधिक कर्मियों को भी राहत माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत महाविद्यालयों में कार्यरत 48,062 शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा।

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।